आकाशवाणी शिमला

07.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / रितेश कपूर / 9:20बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा–प्रदेश में आर.आई.डी.एफ. के तहत 7 सौ 58 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान।
- केंद्रीय बजट में हिमाचल को आर.डी.जी. खत्म किए जाने पर राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देशभर में पिछले 5 वर्षों में दो करोड़ 10 लाख 66 हजार मकान हुए स्वीकृत।
- केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर में बेहतर सुविधाओं के विकास के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आर.आई.डी.एफ के तहत 7 सौ 58 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए शिमला में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों से कहा कि आर.आई.डी. एफ. के तहत विधायकों की कोई डी.पी.आर. जिसे नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित की जा चुकी है और यदि वह डीपीआर किसी अन्य मद से स्वीकृत हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग उस डीपीआर को नाबार्ड से वापिस करने के लिए योजना विभाग को शीघ्र लिखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य में सुधार राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और आने वाले दो वर्षों में 3 हजार करोड़ रुपये हाई–एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च किए जाएंगे। इस बीच आज भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की दूसरे दिन की बैठक आयोजित होंगी।

केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान का प्रावधान खत्म किए जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव लोकभवन भेजा गया है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता–––

डिस्पैच : ***विशेष सत्र के बजाय बजट सत्र बुलाने का सरकार को सुझाव दिया है जिसमें आर.जी.डी. के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया खुद शुक्रवार लोकभवन पहुंचे और विशेष सत्र के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से चर्चा की लेकिन राज्यपाल की ओर से बजट सत्र बुलाने का सुझाव दिया गया है। विपक्ष ने भी विशेष सत्र बुलाने के बजाय बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा किए जाने की बात कही है। ऐसे में अब सत्र को मंजूरी न मिलने से सरकार और लोकभवन के बीच खिंचाव बढ़ने के आसार हैं। वहीं आर.डी.जी. खत्म किए जाने पर सरकार ने कल रविवार को मंत्रिमंडल और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकार आर.जी.डी के मुद्दे पर विपक्ष का भी सहयोग मांग रही ताकि केंद्र सरकार पर बहाली के लिए दबाव बनाया जा सके। ' ' 52 ''***

अनुराग ठाकुर

पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2014 से अब तक मोदी सरकार की बजट दृष्टि समावेशी रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026–27 का केन्द्रीय बजट विकसित भारत का बूस्टर डोज साबित होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12 दशमलव 2 लाख करोड़ किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष में 11 दशमलव 2 लाख करोड़ था। उन्होंने कहा कि बजट का 9 दशमलव 3–7 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए आबंटित किया गया है जिसमें 5 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान है।

पी.एम.ए.वाई–जी–आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन करोड़ 87 लाख से अधिक आवास की मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष 2 फरवरी तक दो करोड़ 95 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्ष में दो करोड़ 10 लाख 66 हजार से अधिक मकानों की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पहली अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य मार्च 2029 तक चार करोड़ 95 लाख मकानों का निर्माण करना है।

राज्यपाल

नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले प्रदेश के एनसीसी कैडेटस ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से लोक भवन शिमला में भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कैडेटस को सम्मानित किया और राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने पर उन्हें बधाई दी। राज्यपाल से भेंट के दौरान कैडेटस ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य के 21 एन.सी.सी. कैडेटस ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर अपनी प्रतिभा अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस वर्ष गणतंत्र दिवस शिविर में बालिका कैडेटस की संख्या अधिक होने पर खुशी जताई।

दर्शन योजना

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वितीय सहायता प्रदान की जा रही है। ऊना जिला के प्रसिद्ध शक्ति पीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर में योजना के तहत बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 55 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता–––

भारत सरकार स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से ऊना जिला में में माता चिंतपूर्ण मंदिर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 55 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुक्ता करे के लिए सीसीटीवी कैमरे इतियादी व विश्राम गृह का निर्माण किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके

आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा ।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कल शिमला में जुब्बल–कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जलापूर्ति, सिंचाई, सीवरेज, सड़कों और सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में जलशक्ति विभाग के तहत करीब 2 सौ 50 करोड़ से अधिक की 94 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

शी हाट

कांगड़ा जिला में श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के समीप शी हाट का निर्माण किया जा रहा है। शी हाट में रेस्टोरेंट सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। धर्मशाला के खंड विकास अधिकारी अभिनीत कात्यायन ने बताया कि श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के साथ स्थित ग्रामीण भंडार को रेनोवेट करके शी हाट का नाम दिया गया है। इस भवन को शी हाट का नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न गतिविधियों का संचालन स्वयं सहायता समूहों, विलेज आर्गेनाजेशन और कलस्टर लेवल फेडरेशन की महिलाओं द्वारा किया जाएगा।

मुख्य समाचार'' एक बार फिर

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा–प्रदेश में आर.आई.डी.एफ. के तहत 7 सौ 58 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान।
- केंद्रीय बजट में हिमाचल को आर.डी.जी. खत्म किए जाने पर राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देशभर में पिछले 5 वर्षों में दो करोड़ 10 लाख 66 हजार मकान हुए स्वीकृत।
- केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर में बेहतर सुविधाओं के विकास के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान।

————————————————